श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : यह तम्बाकूवाला तो नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : तम्बाकू वाला कौन है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह इम्पीरियल टुबैको या इंडियन टुबैको के चेयरमैन जो थे वह आई॰ आई॰ टी॰ के चेयरमैन, उसके बड़े साहब बन गयें हैं ।

अध्यक्ष महोदय: वह तो इसमें नहीं है ।

I was under the impression that it was something on the Order Paper.

SHRI SAMAR GUHA: They are all guided by one a single Central law. The reports should be placed on the Table of the House at the same time...

MR. SPEAKER: As soon as one particular report is ready, it is laid on the Table...

SHRI SAMAR GUHA: Let the hon. Minister say that. I have put question and I have written to you and also to the hon. Minister about the irrigularities in the IIT, serious financial irregulrities...

MR. SPEAKER: He can write to me about any particular item.

SHRI SAMAR GUHA: They should all be placed on the Table of the House on the same day.

MR. SPEAKER: Suppose one of them is delayed, that would mean that the others also will be delayed.

SHRI SAMAR GUHA: Why should the report of only one IIT be placed and why not the reports of the other IITs?

MR. SPEAKER: Suppose one is ready while the others are delayed; why should the one which is ready also be delayed?

SHRI SAMAR GUHA: We should konw it. That is not the procedure. All these five institutions are guided by a single law.

श्री डी॰ पी॰ यादव : मैं इसको दिखवा लूंगा । माननीय सदस्य को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी जो बची हुई रिपोर्टस होंगी वे सभा पटल पर रख दी जायेंगी ।

STATEMENT RE. NON-IMPLEMENTATION OF ASSURANCE GIVEN BY DEPUTY MINISTER OF COMMERCE IN REPLY TO USQ NO. 899 OF 27-7-73 RE. GRANT OF IMPORT ENTITLEMENTS TO SHAREHOLDERS OF MARUTI LTD.

THE MINISTER OF COMMERCE (PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA): Sir, I beg to lay on the Table a statement giving reasons for non-implementation of the assurance given by the Deputy Minister of Commerce in reply to Unstarred Question No. 899 dated the 27th July, 1973 regarding grant of Import Entitlements to shareholders of Maruti Limited. (Placed in Library. See No. LT-8280/74).

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Sir, I would like to mention this. I have got five pending questions and the earliest one was on 14th December, 1972. Sir, the replies are, in all these cases, about Maruti. The replies are like this:

> "Details of permits and despatches up to date information is being collected and will be laid on the Table."

> "Information is being collected and will be laid on the Table of the House."

> "From different sources are being collected and will be laid on the Table."

Sir, on 23rd February, 1973, it has been replied:

> "In so far as all India long-term public financial institutions are concerned, none of them have so far sanctioned.....

Then, they say:

> "The required information is being collected."

I shall conclude and I would sit down by saying this. The question is, the boy has applied for Rs. 7 crores loan from the Central Bank of India.

Mr. Madhu Limaye, the other day, you had asked a question. In reply to that question, the statement is being given.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, असलियत यह है कि दो बार इस प्रश्न को उठाने के बाद मैंने आपके पास प्रिविलेज का सवाल भेजा था और वह विचाराधीन था। अब जब वह प्रिविलेज का सवाल दिया कि एक साल के बाद भी जवाब नहीं आता है तो क्या इसमें सदन की मानहानि नहीं होती है, तब आज ये अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। इसके बारे में दो तीन बातें मैं अर्ज करना चाहता हूं। (1) यह जो हमारी एश्योरेंसेज कमेटी है उसके चेयरमन ने नई लोक सभा के गठन के बाद और कमेटी के गठन के बाद एक भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा कि

"The Committee already laid down the time limit of two months for the implementation of assurances, which was subsequently raised to three months in February 1968, on representation from the Department of Parliamentary Affairs."

पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री के कहने पर दो महीने की मिद्दाद तीन महीने हो गई। अब इसमें तो एक साल से अधिक हो गया और इतना ही नहीं, पुरानी सारी रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पांच प्रश्नों का जवाब 4 साल के बाद भी नहीं आया है। एक सवाल मैंने पूछा था कम्पनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स के एमाल्यूमेंट्स के बारे में। यह मेरा प्रश्न था 4 अगस्त, 1970 का, उसका जवाब अभी तक नहीं आया है। उसी तरह से हल्दिया बरौनी रिफाइनरी की टेकनिकल कमेटी की रिपोर्ट के बारे में एक प्रश्न था, 1 अप्रैल, 1970 से अब तक उसका जवाब नहीं आया। विदेशी कम्पनी, ग्रामोफोन कम्पनी (ई०एम०आई० ग्रुप) के बारे में मैंने तीन प्रश्न पूछे थे।

अध्यक्ष महोदय : पिछली लोक सभा की बात आप कर रहे हैं।

श्री मधु लिमये : यह एक ही, एश्योरेंस की, बात मैं कह रहा हूं। चार चार-साल तक जब प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या अब समय नहीं आया है यह नियम बनाने का कि अगर इस तरह सदन की और सदन की कमेटियों की मानहानि की जायगी तो प्रिविलेज का सवाल उठाया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : 70 वाली बात तो यह है कि उसके बाद दो ढाई साल तक आप खुद नहीं आये।

श्री मधु लिमये : ये जो मेरे प्रश्न थे . . . (व्यवधान) . . .

अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न था, उसके बारे में दो दस्तावेज रखे गये हैं। प्रश्न यह था कि मारुति के जो शेयर-होल्डर्स और डायरेक्टर्स हैं, उनको जो इम्पोर्ट एन्टाइटलमेन्ट दिया गया था, क्या उसमें इन्टरचेन्ज हुआ है ? अध्यक्ष महोदय, इसमें इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है कि मैं कह नहीं सकता। मारुति के अधिकतर इन्वेस्टर्स इस तरह के करप्ट लोग हैं—इस लिये चूंकि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, मैं इसके बारे में आपका मार्गदर्शन चाहता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दोनों सवाल मारुति से सम्बन्धित हैं।

मारुति के बारे में पूछे गये सवालों का जवाब देने में इतनी देर क्यों होनी चाहिए ?

पहले ही जनता के मन में बहुत सन्देह हैं। मैंने श्री चट्टोपाध्याय के दोनों बयानों को पढ़ा है, आप भी इसको पढ़ लीजिये और सन्तोष कर लीजिये। जो समय मांगा गया है और जो समय दिया गया है, क्या वह उचित है, साल भर हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : देने वालों ने दिया और मांगने वालों ने मांगा, मैं बीच में कहां आता हू।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप इस मामले को इस तरह से न टालें। अगर सरकार का रवैया यही है तो हाउस में एशोरेंस देने का कोई मतलब नहीं है, फिर तो हम लोग एशोरेंस कमेटी में नहीं रहना चाहेंगे।

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta—North-East): This is a very vital question which you have allowed to be raised to three months in February, got to know these things, surely it should have a discussion on how assurances are disregarded. We have a committee whose reports possibly we have not been able to discuss, but if this kind of slipshod explanations are given by the Government, surely something is very wrong in this business and we should be given an opportunity to discuss this entire matter of Government assurances, particularly in relation to Maruti, which has a significance of its own. Are we or are we not going to have a discussion in this House in regard to the way in which Government assurances have been managed in a manner which amounts to a contempt of the House?

MR. SPEAKER: Shri Mirdha.

SHRI H. N. MUKERJEE: Are you not going to make any observations on this?

MR. SPEAKER: I cannot make any observation unless I have seen the whole thing. You cannot direct me that the moment you want, I should come out with some observation.

STATEMENT RE NON-IMPLEMENTATION OF ASSURANCE GIVEN IN REPLY TO US Q. No. 1431 OF 1-8-73 RE INQUIRIES AGAINST SHAREHOLDERS OF MARUTI LTD.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: I beg to lay on the Table a statement giving reasons for non-implementation of the assurance given by me in reply te Unstarred Question No. 1431 dated the 1st August, 1973 regarding Inquiries against Shareholders of Maruti Limited for economic offences. (Placed in Library, See No. LT-8281/74).

अध्यक्ष महोदय : यह मामला पहली बार उठा है, ऐसी बात नहीं है। यह मामला कई बार उठा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप जरा मंत्री महोदय के वक्तव्य को देखलें। केवल 100 शेअर होल्डर्स का मामला है। 100 शेयर होल्डर्स के बारे में जानकारी इकट्ठी करने में एक साल से ज्यादा क्यों लगना चाहिए?

12.33 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:—

'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on Friday, the 23rd August, 1974, adopted the following motion in regard to the presentation of the Report of the Joint Committee of the Houses on the Indian Penal Code (Amendment) Bill, 1972:—

"That the time appointed for the presentation of the report of the Joint Committee of the Houses